

मूक पत्रिका

निष्पक्ष, निर्भीक, स्वतंत्र आवाज...

वर्ष - 02 अंक - 237 बेमेतरा, बुधवार 22 अप्रैल 2026 रायपुर एवं बेमेतरा से प्रकाशित कुल पेज - 08 मूल्य - 5 रुपये डाक पंजीयन- दुर्ग/1743290201/2025-27

जारी होगा
सीएम
हेल्पलाइन नंबर

राज्य का कोई भी व्यक्ति किसी भी समय कर सकेगा शिकायत

रायपुर। छत्तीसगढ़ में जल्द सीएम हेल्पलाइन नंबर शुरू होने जा रहा है. 24 घंटे सक्रिय रहने वाले इस हेल्पलाइन नंबर पर राज्य का कोई भी व्यक्ति समस्या या फिर शिकायत कर सकेगा. अफसरों को इन समस्याओं का तय सीमा में निराकरण करना होगा।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने यह जानकारी जशपुर के लिए रवाना होने से पहले मीडिया से चर्चा में दी. उन्होंने बताया की सीएम हेल्पलाइन नंबर पर आने वाली शिकायतों या फिर समस्याओं के निराकरण के लिए समय निर्धारित होगा. अगर तय समय पर शिकायत या समस्या का समाधान नहीं



हुआ तो जिम्मेदार अधिकारी पर कार्रवाई होगी।
छत्तीसगढ़ विधानसभा में निंदा प्रस्ताव के लिए आहुत विशेष सत्र पर

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे देश की महिलाओं के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है. प्रधानमंत्री मोदी महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने जा रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने इसका विरोध किया. इसे लेकर विधानसभा में विशेष सत्र बुलाया गया है।

वहीं पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर विष्णुदेव साय ने कहा कि टीएमसी और ममता बनर्जी को लेकर वहां के लोगों में काफी आक्रोश है. मैंने भी पश्चिम बंगाल का दौरा किया है। लोग बदलाव लाना चाहते हैं, भाजपा की सरकार वहां जरूर बनेगी।

राशन दुकानों
के समय में
हुआ बदलाव

रायपुर। छत्तीसगढ़ में पड़ रही भीषण गर्मी को देखते हुए सरकारी राशन दुकानों के संचालन के समय में बदलाव किया गया है। अब हितग्राहियों को राहत देने के लिए खाद्यान्न वितरण सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक किया जाएगा। नए आदेश के अनुसार दोपहर की तेज गर्मी को ध्यान में रखते हुए राशन दुकानें दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक बंद रहेंगी। इसके अलावा निर्धारित छुट्टियों के दिनों में दुकानें पूरी तरह बंद रहेंगी। पहले राशन दुकानें सुबह 10 बजे

अब सुबह 7 से रात 9 बजे तक मिलेगा अनाज, दोपहर में दो घंटे बंद रहेगी दुकानें



से शाम 5 बजे तक संचालित हो रही थीं, जिससे तेज धूप में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। समय में बदलाव से अब

लोगों को सुबह और शाम के अपेक्षाकृत ठंडे समय में राशन लेने की सुविधा मिल सकेगी।
सरकार के इस फैसले से खासतौर पर बुजुर्गों, महिलाओं और मजदूर वर्ग को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। प्रशासन ने सभी उचित मूल्य दुकानों को नए समय का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं।

केरल के त्रिशूर में पटाखा फैक्ट्री में जोरदार धमाका, 13 लोगों की मौत

केरल। केरल के त्रिशूर जिले में एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहां मुंडाथिकोड इलाके में पटाखा बनाने वाली यूनिट में जोरदार धमाका हुआ, जिसमें कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई, 5 की हालत गंभीर बनी हुई और भी कई लोग घायल हो गए।



बताया जा रहा है कि जिस शेड में यह धमाका हुआ, वहां करीब 40 लोग मौजूद थे। इनमें से कई लोग बुरी तरह झुलस गए हैं और कुछ की हालत गंभीर बनी हुई है। हादसा उस समय हुआ जब आने वाले मशहूर त्योहार त्रिशूर पूरम की तैयारी के लिए पटाखे बनाए जा रहे थे। घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोग तुरंत मदद के लिए पहुंचे और घायलों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया। तस्वीरों में भी लोग खुद रेस्क्यू करते नजर आए। केरल स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के

मुताबिक, अब तक 13 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। पांच शव पूरे मिले, जबकि तीन लोगों के शरीर के हिस्से मलबे से बरामद किए गए। पांच की हालत गंभीर है। केरल के मुख्यमंत्री पिनारayi विजयन ने तुरंत अधिकारियों को निर्देश दिए कि घायलों को हर जरूरी इलाज मुहैया कराया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि जरूरत पड़ने पर दूसरे राज्यों के विशेषज्ञ डॉक्टरों की मदद ली जाए। स्वास्थ्य मंत्री वीणा जॉर्ज ने भी अस्पतालों को अलर्ट पर रखा है और खास इलाज की व्यवस्था

पीएम मोदी ने पटाखा कारखाना हादसे पर दुख जताया

नयी दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने केरल में पटाखा कारखाने में हुई दुर्घटना पर गहरा दुख जताया है और विस्फोट में मृत लोगों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर शोक संदेश में कहा, केरल के त्रिशूर में पटाखा कारखाने में हुई दुर्घटना में हुई जानमाल की हानि के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ। जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। गोलतलब है कि केरल में त्रिशूर के समीप मुंडाथिकोड में पटाखे गोदाम में शाम विस्फोट की घटना में 13 लोगों की मौत हो गयी जबकि कम से कम 40 लोग घायल हो गए।



करने को कहा है। साथ ही 108 एम्बुलेंस समेत अतिरिक्त एम्बुलेंस तैनात करने के निर्देश दिए गए हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक, धमाका दोपहर करीब 3:30 बजे हुआ और उसके बाद भी बीच-बीच में छोटे धमाके होते रहे, जिससे बचाव कार्य में दिक्कत आई। बताया जा रहा है कि यह यूनिट खेतों के बीच बने अस्थायी शेड में चल रही थी। फायर ब्रिगेड, पुलिस और राहत टीम लगातार मौके पर काम कर रही हैं, लेकिन लगातार हो रहे धमाकों के कारण हालात काफी चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं।

धमाके की आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनी गई और आसपास के घरों को भी नुकसान पहुंचा है।
हादसे के कारणों का अभी साफपता नहीं चल पाया है, लेकिन शुरुआती अंदाजा है कि तेज गर्मी इसकी एक वजह हो सकती है। जिला प्रशासन ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं।
कलेक्टर ने मजिस्ट्रियल जांच बैठाई है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई।

आप है ड्रामा पार्टी और केजरीवाल उसके निर्देशक : भाजपा

नयी दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने आबकारी नीति से संबंधित मामले को लेकर दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को लेकर आम आदमी पार्टी (आप) पर निशाना साधा है और उसे ड्रामा पार्टी करार देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उसका निर्देशक बताया है।



भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने मंगलवार को पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए बताया कि केजरीवाल ने गत 13 मार्च को न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा के समक्ष अर्जी लगाई और कहा कि हमें आप पसंद नहीं हैं, आप स्वयं ही इस मामले को त्याग दीजिए।
इसके बाद इस देश की न्यायपालिका के खिलाफ सोचा समझा षड्यंत्र शुरू हुआ। आप ने न्यायमूर्ति शर्मा के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण सोशल मीडिया पर अभियान चलाया तथा न्यायमूर्ति शर्मा और उनके

बच्चों के खिलाफ आरोप लगाए गये। उन्होंने कहा, केजरीवाल ने इस देश की न्यायपालिका की एक महिला सदस्य पर दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन न्यायपालिका पर दबाव बनाने की उनकी राजनीति को खारिज करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने मामले को किसी दूसरी पीठ को स्थानांतरित करने की उनकी याचिका को खारिज कर दिया। इससे यह साबित हो गया है कि आप एक ड्रामा कंपनी है और अरविंद केजरीवाल इस कंपनी के निर्देशक हैं।
उन्होंने कहा, दिल्ली उच्च न्यायालय का कल का आदेश केजरीवाल की दबाव बनाने की चालों को साफतौर पर खारिज कर दिया है और न्यायिक स्वतंत्रता के लिए एक नया पैमाना तय किया है। हम इस फैसले का स्वागत और सराहना करते हैं।

जापान ने हथियारों के निर्यात से प्रतिबंध हटाये

टोक्यो। जापान की सरकार ने अपने हथियार निर्यात नियमों में संशोधन किया है, जिसके तहत हथियारों के निर्यात पर लगायी गयी पाबंदी को हटा लिया गया है। यह जानकारी मंत्रिमंडल के मुख्य सचिव मिनोरू किहारा ने संवाददाता सम्मेलन में दी। उन्होंने कहा, आज, मंत्रिमंडल की बैठक में हथियार निर्यात के तीन सिद्धांतों में से कुछ में संशोधन करने का निर्णय लिया गया। ये निर्णय हमारे देश के आसपास तेजी से बदलती सुरक्षा स्थिति में जापान की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। हमारे देश और इस क्षेत्र में शांति बनाये रखने के लिए हथियार निर्यात को बढ़ावा देना और सहयोगी देशों की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाना आवश्यक है।

उन्होंने कहा कि हथियार निर्यात जापान के रक्षा उद्योग को मजबूत करेगा। उन्होंने कहा, (अन्य देशों को) हथियारों के हस्तांतरण को बढ़ावा देने से रक्षा उद्योग और तकनीकी आधार मजबूत होगा, जो स्व-रक्षा बलों की युद्धक क्षमता को समर्थन देता है। उन्होंने कहा कि जापान शांति के प्रति अपनी प्रतिबद्धता बनाये रखेगा।



मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन पर विवाद, वेणुगोपाल ने दिया नोटिस

नयी दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन को लेकर सियासी विवाद तेज हो गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री का यह संबोधन अपने मूल उद्देश्य से भटककर पूरी तरह राजनीतिक और पक्षपातपूर्ण हो गया।



कांग्रेस संचार विभाग प्रभारी जयराम रमेश ने मंगलवार को बयान जारी कर कहा कि उनके वरिष्ठ सहयोगी और लोकसभा सांसद केसी वेणुगोपाल ने लोकसभा में प्रधानमंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। यह कदम उस संबोधन के बाद उठाया गया है, जो लोकसभा में सरकार की रणनीति को विपक्ष की एकजुटता से झटका लगाने के बाद दिया गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि एक मौजूदा प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम संबोधन हमेशा राष्ट्रीय एकता और विश्वास निर्माण के लिए होता है लेकिन इस बार यह पूरी तरह

राजनीतिक हमलों का मंच बन गया। बयान में कहा गया कि प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कांग्रेस पार्टी पर 59 बार हमला किया, जो इस पद की गरिमा के खिलाफ है। कांग्रेस का कहना है कि प्रधानमंत्री का यह रवैया उनके कार्यकाल पर एक स्थायी दाग के रूप में दर्ज होगा और इससे लोकतांत्रिक परंपराओं को नुकसान पहुंचा है। गौरतलब है कि 18 अप्रैल को मोदी ने राष्ट्र को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़े 131वें संविधान संशोधन विधेयक के पारित न हो पाने पर कांग्रेस और विपक्ष पर कड़ा हमला बोला था।

शेयर बाजारों में शुरुआती कारोबार में तेजी

मुंबई। विदेशों से मिले मिश्रित संकेतों के बीच मंगलवार को घरेलू शेयर बाजारों में शुरुआती कारोबार में तेजी रही। बीएसई का संसेक्स 96.86 अंक की बढ़त के साथ 78,617.16 अंक पर खुला। खबर लिखे जाते समय यह 344.63 अंक (0.44 प्रतिशत) ऊपर 78,864.93 अंक पर था। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की निफ्टी-50 सूचकांक भी 9.70 अंक की मजबूती में 24,374.55 अंक पर खुला और खबर लिखे जाते समय 90.05 अंक यानी 0.37 प्रतिशत की बढ़त के साथ 24,454.90 अंक पर रहा। अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता को लेकर निवेशक सतर्कतापूर्ण लिवाली कर रहे हैं। बाजार में चौतरफा लिवाली देखने को मिल रही है और निवेशक मझौली तथा छोटी कंपनियों में भी पैसा लगा रहे हैं।



आईटी को छोड़कर सभी सेक्टरों के सूचकांक हरे निशान में हैं। रियलटी सेक्टर का सूचकांक फिलहाल डेढ़ फीसदी से ज्यादा ऊपर है। बैंकिंग, वित्त, ऑटो, धातु, एफएमसीजी, टिकाऊ उपभोगा उत्पाद और रसायन समूहों में भी अच्छी तेजी रही।
संसेक्स की कंपनियों में एक्सिस बैंक, अडानी पोर्ट्स और आईसीआईसीआई बैंक के शेयर एक प्रतिशत से अधिक की बढ़त में हैं। एनटीपीसी, टाटा स्टील, एचडीएफसी बैंक, एलएंडटी, बजाज फाइनेंस, एशियन पेंट्स और ट्रेंट के शेयर भी मजबूत बने हुए हैं।

जब तक समझौता नहीं हो जाता अमेरिका ईरानी बंदरगाहों से नहीं हटाएगा नाकेबंदी : ट्रम्प

वाशिंगटन। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जब तक ईरान के साथ कोई समझौता नहीं हो जाता, तब तक अमेरिका ईरानी बंदरगाहों से अपनी नाकेबंदी नहीं हटाएगा।



बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप का यह बयान ऐसे समय आया है जब इस बात को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है कि युद्ध खत्म करने को लेकर दोनों देशों के बीच नयी बातचीत होगी या नहीं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रूथ सोशल' पर लिखा

है कि एक हफ्ता पहले शुरू हुई यह नाकेबंदी ईरान को पूरी तरह तबाह कर रही है और अमेरिका इस संघर्ष में काफी आगे चल रहा है। गौरतलब

है कि अमेरिका और ईरान के बीच अस्थायी संघर्ष-विराम की अवधि बुधवार को खत्म होने वाली है, लेकिन इस बात को कोई निश्चितता

नहीं है कि पाकिस्तान में शांति वार्ता का दूसरा दौर आगे बढ़ेगा या नहीं। बैठक की संभावना को देखते हुए पाकिस्तान की राजधानी में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, लेकिन अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस अभी तक वाशिंगटन से रवाना नहीं हुए हैं, जबकि ईरान का कहना है कि उसने अभी यह तय नहीं किया है कि वह इसमें शामिल होगा या नहीं। वेंस दोनों देशों के बीच होने वाली वार्ता में अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने वाले हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड (सैंटकॉम) के अनुसार जब

से नाकेबंदी शुरू हुई है, अमेरिकी सेना ने 27 जहाजों को वापस लौटाने या किसी ईरानी बंदरगाह पर जाने का निर्देश दिया है।
अमेरिका ने इस संघर्ष के दौरान पहली बार ईरान का झंडा लगे एक मावोवाहक जहाज को भी रोका और जब्त कर लिया। इस जहाज ने रविवार को नाकेबंदी को पार करने की कोशिश की थी। सैंटकॉम द्वारा साझा किए गए वीडियो में कथित तौर पर यह दिखाया गया है कि जहाज पर सैनिकों के उतरने से पहले उसे चेतावनी दी गई थी।

ब्रिटेन और फ्रांस परमाणु क्षमता में वृद्धि करके शुरू कर रहे हैं हथियारों की होड़ : रूस

मास्को। रूस ने कहा है कि ब्रिटेन और फ्रांस अपनी परमाणु क्षमता में वृद्धि करके परमाणु हथियारों की होड़ को जन्म दे रहे हैं। यह परमाणु अप्रसार संधि (एनपीटी) के लक्ष्यों के अनुरूप नहीं है। यह बात रूस के उप विदेश मंत्री अलेक्जेंडर ग्रुशको ने रूसी न्यूज एजेंसी स्पुतनिक के साथ साक्षात्कार में कही। उन्होंने कहा कि फ्रांस के नये सैद्धांतिक दृष्टिकोण कई मायनों में एशिया-प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका की विस्तारित परमाणु निवारण नीति की याद दिलाते हैं और वे खुले तौर पर उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (नाटो)



के संयुक्त परमाणु मिशन में सहायक बनने की योजनाओं को भी उजागर करते हैं।
ग्रुशको ने कहा, ऐसे कदम नाटो के सदस्य देशों की उकसाने वाली सैन्य-परमाणु गतिविधियों के सामान्य पैटर्न के अनुरूप हैं, जो हमारे देश के खिलाफ हैं। ब्रिटेन ने

पहले भी अपनी परमाणु क्षमताओं में वृद्धि की घोषणा की थी और वह भी रूस-विरोधी नारों के तहत। यह अपने आप में हथियारों की होड़ को बढ़ाने का काम करता है, जो न केवल एनपीटी के लक्ष्यों के अनुरूप नहीं है, बल्कि संधि के प्रत्यक्ष दायित्वों के भी सीधे तौर पर विपरीत है।
उन्होंने आगे कहा कि फ्रांसीसी अधिकारियों ने स्थिति को इस तरह प्रस्तुत किया जैसे कि उनका अद्यतन उन्नत परमाणु निवारण सिद्धांत फ्रांस और उसके सहयोगियों की सुरक्षा को मजबूत करेगा।

कलेक्टर ने सभी निर्माण विभागों को कार्यस्थलों पर पेयजल, ओआरएस पैकेट, छाया एवं बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में जल संचय एवं जनभागीदारी पोर्टल, ईएसआरसी अस्पताल की सुविधाएँ, औद्योगिक श्रमिकों की स्वास्थ्य जांच, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण एवं शहरी), बच्चों को विधिक सहायता, भू-अभिलेख अद्यतन, एफआरए नामांतरण, गतिशक्ति योजना, आयुष्मान कार्ड, आंगनवाड़ी पंजीयन, बालिका शौचालय निर्माण, जल जीवन मिशन, पीएम किसान सत्यापन, ट्रांसजेंडर पहचान प्रमाण पत्र, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, ई-ऑफिस ऑनबोर्डिंग एवं मोबाइल टावर स्थापना सहित विभिन्न विषयों पर विस्तार से समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए गए। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ श्री अधिजीत बबन पठारे, अपर कलेक्टर श्री अपूर्व प्रियेश टोपों, डॉ. प्रियंका वर्मा, संयुक्त कलेक्टर श्री राकेश गोलख, श्रीमती पूजा बंसल, डिप्टी कलेक्टर श्री धनराज मरकाम सहित सभी एसडीएम एवं जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।

संपादकीय

अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच टकराव के मोर्चे स्थायी तौर पर बंद होने की संभावना फिलहाल नजर नहीं आ रही है। दो सप्ताह के युद्धविराम की घोषणा के बीच हाल ही में पाकिस्तान के इस्लामाबाद में दोनों पक्षों के बीच हुई शांति वार्ता बेनतीजा रहने से जहां अमेरिका का रुख फिर से आक्रामक हो गया है, वहीं ईरान भी जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार दिख रहा है। पश्चिम एशिया में संघर्ष से उपजे वैश्विक संकट का अगर जल्द समाधान नहीं तलाश गया, तो इसके व्यापक एवं दूरगामी परिणाम सामने आ सकते हैं। इससे न केवल ऊर्जा जरूरतों को पूरा करना बेहद मुश्किल हो जाएगा, बल्कि खाद्य सुरक्षा का संकट गहराने की संभावना भी कई गुना बढ़ जाएगी, जिससे सीधे तौर पर आम आदमी का जीवन स्तर प्रभावित होगा। इसका सबसे ज्यादा असर भारत समेत उन देशों पर पड़ेगा, जो अपनी जरूरतों के लिए आयात पर अधिक निर्भर हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास

पश्चिम एशिया तनाव का असर-महंगाई और गरीबी बढ़ने का बड़ा खतरा

इसका असर दुनिया भर में ऊर्जा के गंभीर संकट के रूप में सामने आएगा। भारत की बात की जाए, तो वह अपनी नब्बे फीसद से अधिक तेल जरूरतों के लिए आयात पर निर्भर है और कच्चे तेल का चालीस फीसद से अधिक तथा एलपीजी का नब्बे फीसद आयात पश्चिम एशिया से किया जाता है। इसके अलावा, उर्वरक आयात का पैतालीस फीसद से अधिक हिस्सा भी इसी क्षेत्र से आता है। इस बात पर गौर करना भी जरूरी है कि भारत के कुल निर्यात का चौदह फीसद और आयात का करीब इक्कीस फीसद व्यापार पश्चिम एशिया से जुड़ा है। ऐसे में यह समझना मुश्किल नहीं होगा कि आने वाले दिनों में देश में किस तरह की स्थिति पैदा हो सकती है। अमेरिका और ईरान के अडिगल रवैये से पश्चिम एशिया में युद्ध के मोर्चे दोबारा खुलने की आशंकाओं के बीच संयुक्त राष्ट्र की रपट में कहा गया है कि भारत में गरीबी दर 23.9 फीसद से बढ़कर 24.2 फीसद

हो सकती है। जबकि वैश्विक स्तर पर 88 लाख लोग गरीबी के जोखिम में आ सकते हैं, जिनमें भारत समेत दक्षिण एशिया के लोग सबसे अधिक होंगे। इस संकट के बाद देश में गरीबी में रहने वालों की संख्या 35.40 करोड़ तक पहुंच सकती है, जो पहले 35.15 करोड़ थीं।[जहिर है कि देश की आबादी के एक बड़े हिस्से के लिए जीवन-यापन से संबंधित नई मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी। इसमें दराय नहीं कि देश में मौजूदा परिस्थितियों से निपटने के लिए सरकार की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन इससे निश्चित तौर पर सरकारी बजट पर अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है और ऐसे में ज्यादा दिन तक स्थिति को संभालना आसान नहीं होगा। ऐसे में जरूरी है कि सरकार ऊर्जा के नए स्रोत तलाशने के साथ-साथ आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए वैकल्पिक उपायों पर गंभीरता से काम करे, ताकि संभावित संकट के असर को कम किया जा सके।

वैश्विक तनाव के बीच भारत की सधी हुई चाल,ऑस्ट्रिया के साथ सहयोग बढ़ाकर मोदी ने किया कमाल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चांसलर स्टॉकर का स्वागत करते हुए इसे विशेष अवसर बताया और इस बात पर जोर दिया कि यूरोप के बाहर अपनी पहली यात्रा के लिए भारत को चुनना ऑस्ट्रिया की भारत के प्रति गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह यात्रा ऐसे समय में हुई है जब भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते के बाद आर्थिक और रणनीतिक सहयोग के नए अवसर सामने आए हैं।

(नीरज कुमार दुबे)

भारत और ऑस्ट्रिया के संबंध पहले से ही अवसररचना, नवाचार और सतत विकास के क्षेत्रों में मजबूत रहे हैं। दिव्ली मेट्रो और अटल सुरंग जैसे महत्वपूर्ण परियोजनाओं में ऑस्ट्रिया की तकनीकी विशेषज्ञता का महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

भारत और ऑस्ट्रिया के बीच संबंधों को नई दिशा देने वाली एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक पहल के तहत ऑस्ट्रिया के चांसलर क्रिश्चियन स्ट्रिंकर की भारत यात्रा ऐतिहासिक मानी जा रही है। लगभग चार दशकों के बाद किसी ऑस्ट्रियाई चांसलर का भारत आगमन न केवल द्विपक्षीय संबंधों की मजबूती का संकेत है, बल्कि यह वैश्विक परिदृश्य में बदलती प्राथमिकताओं के बीच नई साझेदारी के निर्माण का भी प्रतीक है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चांसलर स्टॉकर का स्वागत करते हुए इसे विशेष अवसर बताया और इस बात पर जोर दिया कि यूरोप के बाहर अपनी पहली यात्रा के लिए भारत को चुनना ऑस्ट्रिया की भारत के प्रति गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह यात्रा ऐसे समय में हुई है जब भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते के बाद आर्थिक और रणनीतिक सहयोग के नए अवसर सामने आए हैं।

भारत और ऑस्ट्रिया के संबंध पहले से ही अवसररचना, नवाचार और सतत विकास के क्षेत्रों में मजबूत रही हैं। दिव्ली मेट्रो और अटल सुरंग जैसे महत्वपूर्ण परियोजनाओं में ऑस्ट्रिया की तकनीकी विशेषज्ञता का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसके अलावा रेलवे परियोजनाओं, रोपवे, स्वच्छ ऊर्जा और शहरी विकास जैसे क्षेत्रों में भी ऑस्ट्रियाई कंपनियों की सक्रिय भागीदारी रही है।

दोनों देशों के बीच हुए 15 करार

इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कुल पंद्रह महत्वपूर्ण समझौते और पहलें सामने आईं, जो रक्षा, प्रौद्योगिकी, व्यापार, नवाचार और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों को कवर करती हैं। इनमें सबसे प्रमुख है आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त कार्य समूह की स्थापना का प्रस्ताव, जो वैश्विक स्तर पर आतंकवाद से निपटने में रणनीतिक सहयोग को मजबूत करेगा।

रक्षा क्षेत्र में भी सहयोग को नई गति देने के लिए सैन्य मामलों में सहयोग पर एक आशय पत्र पर सहमति बनी है। इसके तहत रक्षा उद्योग, नीति संवाद, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण को बढ़ावा दिया जाएगा। यह पहल भारत और यूरोप के बीच हाल ही में हुए सुरक्षा सहयोग की भी मजबूती प्रदान करेगी।

आर्थिक संबंधों को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से एक फास्ट ट्रैक तंत्र स्थापित करने की घोषणा की गई है, जिससे दोनों देशों की कंपनियों और निवेशकों को आने वाली समस्याओं का शीघ्र समाधान किया जा सकेगा। इससे व्यापार को सुगम बनाने और निवेश को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है।

सांस्कृतिक और रचनात्मक क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए ऑडियो विजुअल सह उत्पादन समझौता किया गया है, जिससे दोनों देशों के फिल्म उद्योग के बीच संयुक्त निर्माण और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा मिलेगा। खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में भी एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ है, जिसके तहत वैज्ञानिक सहयोग, मानकों के आदान प्रदान और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा किया जाएगा। इससे कृषि और खाद्य उत्पादों के व्यापार को भी मजबूती मिलेगी।

इसके अलावा, दोनों देशों के बीच कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए एक संयुक्त आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसमें प्रशिक्षुता प्रणाली, ज्ञान साझा करने और योग्यता की पारस्परिक मान्यता पर जोर दिया गया है। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए संरचित संवाद शुरू करने और तकनीकी विश्वविद्यालयों के माध्यम से भारतीय छात्रों के लिए नए

कार्यक्रम की ओर से जारी एक रपट में कहा गया है कि अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच टकराव से उत्पन्न ख़लात के कारण भारत में पच्चीस लाख लोगों के गरीबी की जद में आने का खतरा है। इस आकलन का आधार यह है कि हेर्मुज जलमार्ग के बाधित होने से जहां ईंधन, मालभाड़ा और कच्चे माल की लागत बढ़ रही है, वहीं लोगों की आजीविका कमजोर हो रही है, घरेलू क्रय शक्ति घट रही है और खाद्य असुरक्षा बढ़ रही है। गौरतलब है कि अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच टकराव के मोर्चे स्थायी तौर पर बंद होने की संभावना फिलहाल नजर नहीं आ रही है। दो सप्ताह के युद्धविराम की घोषणा के बीच हाल ही में पाकिस्तान के इस्लामाबाद में दोनों पक्षों के बीच हुई शांति वार्ता बेनतीजा रहने से जहां अमेरिका का रुख फिर से आक्रामक हो गया है, वहीं ईरान भी जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार दिख रहा है। ऐसे में अगर हेर्मुज जलमार्ग लंबे समय तक बंद रहा, तो

कार्यक्रम की ओर से जारी एक रपट में कहा गया है कि अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच टकराव से उत्पन्न ख़लात के कारण भारत में पच्चीस लाख लोगों के गरीबी की जद में आने का खतरा है। इस आकलन का आधार यह है कि हेर्मुज जलमार्ग के बाधित होने से जहां ईंधन, मालभाड़ा और कच्चे माल की लागत बढ़ रही है, वहीं लोगों की आजीविका कमजोर हो रही है, घरेलू क्रय शक्ति घट रही है और खाद्य असुरक्षा बढ़ रही है। गौरतलब है कि अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच टकराव के मोर्चे स्थायी तौर पर बंद होने की संभावना फिलहाल नजर नहीं आ रही है। दो सप्ताह के युद्धविराम की घोषणा के बीच हाल ही में पाकिस्तान के इस्लामाबाद में दोनों पक्षों के बीच हुई शांति वार्ता बेनतीजा रहने से जहां अमेरिका का रुख फिर से आक्रामक हो गया है, वहीं ईरान भी जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार दिख रहा है। ऐसे में अगर हेर्मुज जलमार्ग लंबे समय तक बंद रहा, तो

अवसर उपलब्ध कराने की पहल भी की गई है।

इस यात्रा के दौरान स्टार्टअप सहयोग को बढ़ाने, साइबर सुरक्षा संवाद शुरू करने, अंतरिक्ष उद्योग में संयुक्त सेमिनार आयोजित करने और वर्किंग वॉलंडे कार्यक्रम को लागू करने जैसी घोषणाएं भी की गईं। उच्च प्रौद्योगिकी जैसे क्वांटम तकनीक, मशीन लर्निंग, जल शोधन और सामग्री विज्ञान में संयुक्त अनुसंधान को साझेदारी का मुख्य आधार बनाया गया है।

प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर यह भी कहा कि भारत की प्रतिभा और ऑस्ट्रिया की नवाचार क्षमता मिलकर वैश्विक स्तर पर भरोसेमंद तकनीक और आपूर्ति श्रृंखला विकसित कर सकती है। उन्होंने रक्षा, सीमांकडवर, जैव प्रौद्योगिकी और क्वांटम क्षेत्रों में सहयोग की अपार संभावनाओं को रेखांकित किया। इसके अलावा, मानव संसाधन के क्षेत्र में भी दोनों देशों ने प्रगति की दिशा में कदम बढ़ाया है। वर्ष 2023 में हुए प्रवासन और गतिशीलता समझौते के तहत अब नर्सिंग क्षेत्र में



भी सहयोग को विस्तार दिया जाएगा। युवा आदान प्रदान को प्रोत्साहित करने के लिए वर्किंग वॉलंडे कार्यक्रम की शुरुआत की गई है।

साथ ही वैश्विक परिदृश्य पर चर्चा करते हुए दोनों देशों ने इस बात पर सहमति जताई कि सैन्य संघर्ष किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। चाहे यूक्रेन का संकट हो या पश्चिम एशिया की स्थिति, दोनों देशों ने स्थायी और शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन किया। साथ ही वैश्विक संस्थाओं में सुधार और आतंकवाद के पूर्ण उन्मूलन की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया।

हम आपको एक बार फिर बता दें कि ऑस्ट्रिया भारत के लिए एक महत्वपूर्ण यूरोपीय साझेदार है। यह मध्य और पूर्वी यूरोप में प्रवेश का एक प्रमुख द्वार है और हरित प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा तथा उन्नत

भारत की रणनीतिक बढ़त को और मजबूत करेगी, क्योंकि उन्नत तकनीक, रक्षा सहयोग और आर्थिक निवेश के माध्यम से भारत क्षेत्रीय नेतृत्व को और प्रभावी ढंग से स्थापित कर सकेगा। इससे न केवल भारत की सुरक्षा क्षमताएं बढ़ेंगी, बल्कि वह क्षेत्र में स्थिरता, विकास और संतुलन बनाए रखने में भी अधिक सक्षम भूमिका निभा सकेगा।

बहरहाल, ऑस्ट्रिया के चांसलर की भारत यात्रा ने यह स्पष्ट कर दिया है कि दोनों देशों के संबंध अब पारंपरिक सहयोग से आगे बढ़कर नवाचार केंद्रित और भविष्य उन्मुख साझेदारी की ओर अग्रसर हैं। दोनों देशों ने मिलकर एक ऐसे सहयोग मॉडल की नींव रखी है जो न केवल द्विपक्षीय हितों का संभेगा, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी स्थिरता और प्रगति में योगदान देगा। (इस लेख में लेखक के अपने विचार हैं ।)

तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दहलीज पर भारत, लेकिन रास्ते में ये बड़ी चुनौतियां

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की एक रपट के अनुसार, वर्ष 2024 में भारत की अर्थव्यवस्था का आकार लगभग 3.7 ट्रिलियन डालर था। वर्तमान में अमेरिका और चीन क्रमशः पहली और दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। आर्थिक विशेषज्ञों और संस्थाओं के आकलन के अनुसार, भारत वर्ष 2030 में जर्मनी को पीछे छोड़कर तीसरे स्थान पर पहुंच सकता है। मगर इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए भारत के सामने अनेक अवसरों के साथ-साथ कई चुनौतियां भी मौजूद हैं।

(अजय जोशी)

भारत की आधुनिक आर्थिक प्रगति की शुरुआत वर्ष 1991 के आर्थिक सुधारों से मानी जाती है। उस समय देश गंभीर भुगतान संतुलन संकट से जूझ रहा था और विदेशी मुद्रा भंडार केवल कुछ सप्ताह के आयात के बराबर ही रह गया था।

वैश्विक परिदृश्य में भारत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में उभर रहा है। बढ़ता उपभोक्ता बाजार, आर्थिक वृद्धि में इजाफा और तकनीकी प्रगति से देश विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सम्मिलित हो चुका है। भारत ने जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का स्थान हासिल कर लिया है और अब तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है।

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की एक रपट के अनुसार, वर्ष 2024 में भारत की अर्थव्यवस्था का आकार लगभग 3.7 ट्रिलियन डालर था। वर्तमान में अमेरिका और चीन क्रमशः पहली और दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। आर्थिक विशेषज्ञों और संस्थाओं के आकलन के अनुसार, भारत वर्ष 2030 में जर्मनी को पीछे छोड़कर तीसरे स्थान पर पहुंच सकता है। मगर इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए भारत के सामने अनेक अवसरों के साथ-साथ कई चुनौतियां भी मौजूद हैं।

भारत की आधुनिक आर्थिक प्रगति की शुरुआत वर्ष 1991 के आर्थिक सुधारों से मानी जाती है। उस समय देश गंभीर भुगतान संतुलन संकट से जूझ रहा था और विदेशी मुद्रा भंडार केवल कुछ सप्ताह के आयात के बराबर ही रह गया था। इस स्थिति से उबरने के लिए सरकार ने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीतियां अपनाईं। इन सुधारों के परिणामस्वरूप विदेशी निवेश बढ़ा, उद्योगों को नई ऊर्जा मिली और भारत का वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ाव मजबूत हुआ। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 1991 में भारत का

सकल घरेलू उत्पाद लगभग 270 अरब डालर था, जो वर्ष 2000 में करीब 470 अरब डालर तक पहुंच गया। वर्ष 2010 में यह लगभग 1.7 ट्रिलियन डालर हो गया। जबकि 2020 में भारत की अर्थव्यवस्था करीब 2.9 ट्रिलियन डालर थी। इस तरह वर्ष 2024 में यह लगभग 3.7 ट्रिलियन डालर के आसपास पहुंच चुकी है। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि पिछले तीन दशकों में भारत की अर्थव्यवस्था काफी तेजी से बढ़ी है।

भारत की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की संभावना के पीछे मजबूत आधार हैं। देश में विशाल जनसंख्या के अनुरूप बड़ा उपभोक्ता बाजार है। भारत विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन गया है। अर्थव्यवस्था में मध्यम वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। 'मैकेंजी ग्लोबल इंस्टीट्यूट' की एक रपट के अनुसार, भारत का मध्य वर्ग तेजी से बढ़ रहा है और अनुमान है कि वर्ष 2030 तक इस वर्ग की संख्या पचास करोड़ से अधिक हो सकती है। इसके अलावा भारत के सकल घरेलू उत्पाद में निजी उपभोग का योगदान लगभग साठ फीसद है, जो आर्थिक वृद्धि का महत्वपूर्ण आधार है। देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा युवा है। विश्व बैंक की रपट के अनुसार, भारत की करीब पैसड़ फीसद आबादी 35 वर्ष से कम आयु की है। इसलिए यदि भारत अपने युवा कार्यबल को उचित शिक्षा और कौशल प्रदान करे, तो यह आर्थिक विकास के लिए बड़ा अवसर बन सकता है।

देश में डिजिटल क्रांति ने आर्थिक गतिविधियों को नई दिशा प्रदान की है। ट्राई और इंटरनेट पंड मोबाइल एप्लोसिएशन आफ इंडिया के अनुसार, भारत में 85 करोड़ से अधिक इंटरनेट उपयोगकर्ता हैं और यह संख्या निरंतर बढ़ रही है। इसके अलावा यूपीआइ की डिजिटल भुगतान प्रणाली ने वित्तीय लेन-देन को बहुत आसान बना दिया है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के आंकड़ों से पता चलता है कि वर्ष 2023 में डिजिटल भुगतान प्रणाली के माध्यम से करीब 180 लाख करोड़ रुपए से अधिक का लेन-देन हुआ।

भारत आज दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल भुगतान बाजारों में से एक है। यहां नवउद्यम भी तेजी से विकसित हुआ हैं। देश में दिसंबर, 2025 तक खीपीआइआइटी-मान्यता प्राप्त नवउद्यमों की संख्या दो लाख से अधिक हो गई है और इस मामले में भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर आता है। इन नवउद्यमों ने लगभग 21 लाख प्रत्यक्ष रोजगार पैदा किए हैं और इनमें 'ग्लिनकार्स' की संख्या 120 से ऊपर पहुंच गई है। फिनटेक, ई-वाणिज्य, स्वास्थ्य, तकनीक और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में नवउद्यम तेजी से नवाचार कर रहे हैं। देश में बुनियादी ढांचे के विकास में बड़े पैमाने पर निवेश किया जा रहा है। वर्ष 2024-25 के आम बजट में लगभग 11.1 लाख करोड़ रुपए आधारभूत ढांचे के विकास के लिए आबंटित किए गए। आधारभूत ढांचे की उपलब्धता और इससे जुड़ी भावी परियोजनाओं की दृष्टि से भी भारत का तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बनने की संभावनाओं को बल मिलता है।

सड़क परिवहन मंत्रालय और भारतीय रेलवे के आंकड़ों के अनुसार, देश में 1.46 लाख किलोमीटर से अधिक राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। रेलवे नेटवर्क लगभग 68,000 किलोमीटर लंबा है। यह दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। देश को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने के लिए भी कई उपाय किए गए हैं। 'मेक इन इंडिया' और उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन की योजनाओं के माध्यम से सरकार उद्योगों को प्रोत्साहित कर रही है। इतना सब कुछ होते हुए दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए भारत की राह में बाधाएं भी कम नहीं हैं।

इनमें बेरोजगारी और रोजगार सृजन एक बड़ी चुनौती है। देश में हर वर्ष लगभग एक से डेढ़ करोड़ युवा रोजगार बाजार में प्रवेश करते हैं। सेंटर फार मानिटर्सिंग इंडियन इकोनामी के अनुसार, भारत की बेरोजगारी दर सात से आठ फीसद के आसपास रहती है। अगर पर्याप्त रोजगार सृजन नहीं होता है, तो यह एक बड़ी आर्थिक और सामाजिक चुनौती बन जाएगी। देश की लगभग 42 फीसद आबादी कृषि पर

निर्भर है, लेकिन सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान केवल 15-16 फीसद ही है। आज भी सिंचाई और आधुनिक तकनीक की कमी कृषि क्षेत्र में उत्पादन को प्रभावित करती है। देश में आर्थिक विकास के बावजूद आय असमानता बढ़ रही है। आक्सफैम की समानता रपट के अनुसार, भारत के शीर्ष दस फीसद लोग संघट का लगभग 70 फीसद संपत्ति को नियंत्रित करते हैं, जबकि निचले तीस फीसद लोगों के पास बहुत कम संपत्ति है। यह असमानता भी सामाजिक और आर्थिक संतुलन के लिए बड़ी चुनौती बनती जा रही है। भारत में साक्षरता दर लगभग 77 फीसद है, जबकि उच्च शिक्षा में नामांकन दर करीब 28 फीसद है। कई उद्योगों का कहना है कि बड़ी संख्या में स्नातक युवाओं के पास आवश्यक कौशल की कमी है। इसलिए कौशल विकास कार्यक्रमों को मजबूत करना आवश्यक है। इसके अलावा तेजी से बढ़ते औद्योगीकरण और शहरीकरण के कारण पर्यावरणीय समस्याएं भी लगातार बढ़ रही हैं।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में कई भारतीय शहर भी शामिल हैं। नीति आयोग की जल रपट (2018) के आंकड़ों से पता चलता है कि देश के लगभग साठ करोड़ लोग जल संकट का सामना कर सकते हैं। यह समस्या भी तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह में बाधा पैदा कर सकती है। यही नहीं, अमेरिका-इजराइल और ईरान युद्ध की स्थिति विश्व की सभी अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित कर रही है और भारत भी इससे अछूता नहीं है। इस पहलू पर भी गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। कुल मिलाकर देश को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए शिक्षा और कौशल विकास में निवेश को बढ़ावा देना, विनिर्माण और निर्यात को प्रोत्साहित करना, कृषि सुधार और ग्रामीण विकास, तकनीकी नवाचार, डिजिटल अर्थव्यवस्था का विस्तार तथा पर्यावरणीय संतुलन एवं टिकाऊ विकास की दिशा में प्रभावी कदम उठाने होंगे।

जनशिकायतों के त्वरित निराकरण हेतु 1 मई से 10 जून तक 15-20 पंचायतों के क्लस्टरों में लगेगा जनसमस्या निवारण शिविर: कलेक्टर डॉ संजय कन्नौजे

30 अप्रैल तक विशेष अभियान चलाकर सभी पेंडिंग को मुग्तान करने के निर्देश

राजस्व आरबीसी 6-4 प्रकरण, मनरेगा मजदूरी सहित अन्य हितग्राहीमूलक लंबित मुग्तान होंगे विलयर

महतारी वंदन के हितग्राहियों का अभियान चलाकर ईकेवायसी करने के निर्देश

निर्माण कार्यों को गुणवत्तापूर्ण टाईम लिमिट में पूर्ण करने के निर्देश

खेलभाटा हॉस्टल जीणोंद्वार कार्य की धीमी प्रगति पर कलेक्टर ने इंजीनियर को फ़टकार लगाई

भीमभौरी में महिला मोर्चा को नई कमान, रेखा पोषण सिन्हा बनीं मंडल अध्यक्ष

कार्यकर्ताओं में उत्साह, संगठन को मिलेगी नई गति

बेमेतरा/मूक पत्रिका

भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा में संगठनात्मक मजबूती के तहत भीमभौरी मंडल को नई नेतृत्वकारी जिम्मेदारी दी गई है। भाजपा महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष प्रज्ञा निर्वाणी की अनुशंसा एवं वरिष्ठ पदाधिकारियों की सहमति से क्षेत्र की सक्रिय जनप्रतिनिधि एवं वर्तमान जनपद सदस्य रेखा पोषण सिन्हा को भीमभौरी मंडल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति से क्षेत्र में हर्ष का माहौल है और कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है।रेखा पोषण सिन्हा लंबे



समय से सामाजिक, धार्मिक एवं आध्यात्मिक गतिविधियों में सक्रिय रही हैं। उनके परिवार की भी क्षेत्र में समाजसेवा की सशक्त पृष्ठभूमि रही है, जिसका लाभ संगठन को निश्चित रूप से मिलेगा। एक सक्रिय और जमीनी स्तर पर काम करने वाली युवा नेतृत्वकर्ता के रूप में उनकी पहचान रही है, जिससे कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार हुआ है।नवनियुक्त मंडल अध्यक्ष रेखा पोषण सिन्हा ने कहा कि पार्टी ने जो विश्वास जताया है, उस पर वे पूरी

कलेक्टर डॉ कन्नौजे ने दुर्गा पैकरा को दी अनुकंपा नियुक्ति



सारंगढ़-बिलाईगढ़/मूक पत्रिका

कलेक्टर डॉ संजय कन्नौजे ने कलेक्टर कक्ष में दुर्गा पैकरा को भूत्व पद के लिए अनुकंपा नियुक्ति पत्र प्रदान किया। यह नियुक्ति उनके पिता गनेशराम पैकरा के आकस्मिक निधन हो जाने पर उनके पुत्री दुर्गा पैकरा को प्रदान की गई। कलेक्टोरेट सारंगढ़ में गनेशराम पैकरा भूत्व के पद पर कार्यरत थे। निधन के कुछ महिनो में ही अनुकंपा नियुक्ति पत्र मिलने से परिवार को संबल मिला है।

राम चिचोली में 22 अप्रैल को होगा रात्रिकालीन जन चौपाल

सारंगढ़-बिलाईगढ़/मूक पत्रिका

कलेक्टर डॉ संजय कन्नौजे की उपस्थिति में बिलाईगढ़ विकासखंड के ग्राम चिचोली में (भटगांव से विरारोड में सलिहाघाट के पास) 22 अप्रैल को रात्रिकालीन जन चौपाल का आयोजन किया जाएगा। इस शिविर में जिले और ब्लॉक स्तर के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहेंगे। इस दौरान जिले के नागरिक अपनी मांग, शिकायत भी कलेक्टर को प्रस्तुत कर सकते हैं।

खनिज विभाग का मिलीभगत खेल,, कागज पर वैध दिखा कर राजस्व को लग गए करोड़ों का चुना

केजड़ीवाल क्रशर संचालक की मनमानी, लीज पर खनन नहीं फिर भी करोड़ों की रॉयल्टी पर्ची जारी

सारंगढ़/मूक पत्रिका

सारंगढ़ जिले में गौण खनिज के अवैध कारोबार का एक और बड़ा मामला सामने आया है। केजड़ीवाल क्रशर संचालक पर आरोप है कि खनिज विभाग से स्वीकृत चिन्हांकित लीज स्थान पर आज तक एक फ़वड़ा खनन नहीं हुआ, लेकिन कागजों में करोड़ों रुपये की रॉयल्टी पर्ची जारी हो चुकी है। खनिज विभाग मिलीभगत का जीता जागता सबूत केजड़ीवाल क्रेशर उद्योग है जहां पर देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि खनिज विभाग और केजड़ीवाल संचालक द्वारा शासन को किस तरह से चूना लगाया जा रहा है। खनिज विभाग में फ़िक्सिंग रेट तय कर के पट्टे दारो को रायल्टी पर्ची जारी कर देते हैं। फिर संचालक द्वारा रॉयल्टी पर्ची को बाजार में शासन द्वारा निर्धारित मूल्य से चार गुना अधिक बढ़ा कर बेचा जाता है जबकि नियमानुसार गलत है। और ऐसे ही कई चुना पत्थर खदान है जो पूरी तरह से अवैध है केवल शासन के कागज पर वैध है



क्या है पूरा मामला –1. लीज पर सत्राटा: खनिज विभाग के रिकॉर्ड में ख.न. 364/1,366/2,365/1,347/2,362/1,36 2/3 कुल रकबा 1.234 है. इस शिविर में जिले और ब्लॉक स्तर के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहेंगे। इस दौरान जिले के नागरिक अपनी मांग, शिकायत भी कलेक्टर को प्रस्तुत कर सकते हैं।

22/06/ 2040 तक वैध खनन अनुमति मिला है जिस खसरा नंबर पर केजड़ीवाल क्रशर को लाइसेन्स/पत्थर खनन की लीज दी गई है, वहां मौका-मुआयना करने पर खनन का कोई कार्य नहीं मिला। जमीन जस की तस है। और विभाग

द्वारा लाखों करोड़ों की रॉयल्टी पर्ची जारी किया गया जिससे सफ़सफ़ापता चलता है कि विभाग माफ़िश्रिआओं के वश में रह कर काम करते हैं।

2. रॉयल्टी में खेल: चौकाने वाली बात ये है कि बिना खनन के ही इसी लीज से करोड़ों रुपये

की रॉयल्टी पर्ची कट चुकी है। आशंका है कि दूसरी अवैध खदनों से निकाले गए माल को वैध दिखाने के लिए इस लीज की पर्चियों का इस्तेमाल किया जा रहा है।

नियम क्या कहते हैं –छत्तीसगढ़ गौण

खनिज नियम 2015 के तहत लीज क्षेत्र से बाहर खनन करना और बिना उत्पादन के रॉयल्टी पर्ची जारी करना दोनों ही दंडनीय अपराध हैं। इसमें लीज निरस्त करने के साथ-साथ जुर्माना और स़द्धक्रका भी प्रावधान है।

ग्रामीणों में आक्रोश –स्थानीय लोगों का कहना है कि क्रशर संचालक की मनमानी से शासन को करोड़ों के राजस्व का नुकसान हो रहा है। पर्यावरण और सड़कें खराब हो रही हैं, लेकिन कागजों में सब «वैध» दिख रहा है।

प्रशासन का पक्ष –इस संबंध में जिला खनिज अधिकारी से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन फ़िलहाल उनका बयान नहीं मिल सका। सूत्रों के अनुसार शिकायत मिलने पर भौतिक सत्यापन और छ़वक्क़ सर्वे कराया जाएगा।

अब आगे क्या –अगर भौतिक सत्यापन में आरोप सही पाए गए तो लीज निरस्त करने, जारी रॉयल्टी की वसूली और आपराधिक प्रकरण दर्ज करके की कार्रवाई बनती है। अब देखने वाली बात होगी कि खनिज विभाग कार्रवाई करता है या फिर मामला फ़इलों में दब जाता है।

प्रादेशिकी

क्या रायगढ़ बन गया है मानव तस्करी का ‘हब’? गुमशुदगी के आंकड़ों ने उड़ाई नींद, सैकड़ों लोग गायब, सभी नहीं लौटते वापस, खोजबीन भी बंद

हर साल सैकड़ों बच्चे, महिलाएं और पुरुष हो जाते हैं गुम, बच्चों की वापसी भी शतप्रतिशत नहीं

रायगढ़/मूक पत्रिका

मानव तस्करी को लेकर शोर बहुत मचता है। पहले की तरह अब भी ऐसे कई दलाल हैं जो इस काम में सक्रिय हैं। काम का लालच देकर बड़े शहरों में गुलाम बनाने का सिलसिला जारी है। हर साल सैकड़ों की संख्या में बच्चे, महिलाएं और पुरुष गायब हो रहे हैं, जिनमें से सबकी वापसी नहीं हो पाती। मतलब बड़ी संख्या में लोग गायब हो रहे हैं। पिछड़े आदिवासी क्षेत्रों में मानव तस्करी का काम बड़े जोरों से हो रहा था। जागरूकता और पुलिसिया कार्रवाई से कुछ हद तक लगाम लगी है लेकिन अभी भी बच्चों, महिलाओं और पुरुषों के गायब होने का



सिलसिला जारी है। 2023 से अब तक जिले से करीब 483 बच्चे गायब हुए थे। इनमें से 434 को ढूंढकर वापस लाया जा चुका है। लेकिन 49 बच्चों का पता नहीं चल सका है। कोई घर छोड़कर चला जाए तो वह किसी न किसी दिन वापस आता है। इन बच्चों में नाबालिग बच्चियों की संख्या अधिक है जिनको कोई शादी का झांसा देकर भगा ले जाता है। कई बच्चे अचानक से गायब हो जाते हैं। यही नहीं महिलाओं और पुरुषों के मामले में भी आंकड़े चिंताजनक हैं। 2023 से फरवरी 2026 तक रायगढ़ जिले से 1545 महिलाएं गायब हुई हैं। इनमें से पुलिस ने 1191 को सकुशल

खोज निकाला। कई महिलाएं शारीरिक शोषण का शिकार हो जाती हैं। कई तो बड़े शहरों में घरेलू काम करने के लिए बेच दी जाती हैं। तीन सालों में 354 महिलाओं का पता नहीं चल सका। पुरुषों के गायब होने के पीछे कोई तर्क काम नहीं करता। इस अवधि में रायगढ़ जिले से 691 पुरुषों के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इसी अवधि में 534 को खोज लिया गया या वे खुद ही वापस आ गए।

मानव तस्करी की आशंका अब भी-इतनी संख्या में नाबालिगों, महिलाओं और पुरुषों का गायब होना सामान्य नहीं है। मानव तस्करी की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता। पहले की तरह नहीं लेकिन अब भी लोगों के गुम होने का सिलसिला जारी है। बड़े शहरों में घरेलू काम कराने के बहाने लालच दिया जाता है।

निगम में नाबालिगों से कराया काम, श्रम विभाग की जांच में सवालिया निशान?

प्राथमिक जांच में क्लीनचिट, अब सफ़ाई ठेकेदार से कर्मियों के डेटाबेस की मांग



खुब हल्ला मचा था।परन्तु गड़बड़ी यही तक नहीं थी।बताया जा रहा है कि शहर को साफ दिखाने और स्वच्छता रैंकिंग में अच्छा प्रदर्शन करने निगम द्वारा संबंधित सफ़ाई ठेकेदार को तीस अतिरिक्त कर्मचारी

नाबालिगों के उम्र की जांच करने की जहमत उठाई।

और न ही इनके दस्तावेज खंगाले गए।मामले की शिकायत जब श्रम विभाग तक पहुंचा।तब तलक मौके से नाबालिग सफ़ाई कर्मी फ़ार हो चुके थे।वहहरहाल 20 दिनों से अधिक हो चुके इस घटना के बाद मानो श्रम विभाग महज औपचारिकता पूरी करने में लगा है।तो क्या विभाग के ऐसे जिम्मेदार अधिकारियों से श्रम कानून का कड़ाई से पालन कराए जाने की उम्मीद जताई जा सकती है।

श्रम विभाग की नहीं दिलचस्पी

यदि श्रम विभाग इस मामले को लेकर गंभीर होता तो अब तक निगम और संबंधित ठेकेदार से

सफ़ाईकर्मियों की पूरी जानकारी मंगाई जा चुकी होती। लेकिन विभाग प्रारंभिक जांच में किसी प्रकार की खामी न मिलने की बात कहकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ल झाड़ता नजर आया।विभाग की माने तो 14 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे कार्य कर सकते है।वही अब अधिकारियों से मामले में सवाल-जवाब किए जाने के बाद अब विभाग द्वारा ठेकेदार से सफ़ाईकर्मियों का पूरा डेटाबेस मंगाने की बात कही जा रही है।

क्या कहते है घनश्याम पाणिग्रही जिला श्रमायुक्त

प्रारंभिक जांच में कोई खामी नहीं मिली थी।ठेकेदार से सफ़ाईकर्मियों का डेटाबेस मंगाया जाएगा।

जंगल में अतिक्रमण रोक रहे डिप्टी रेंजर और वन रक्षक को ग्रामीणों ने कुल्हाड़ी दिखाकर धमकाया, मारपीट का किया प्रयास.. FIR दर्ज



सोमवार को वह चोटीगुड़ा वन रक्षक सुभाष कुमार कर्ष के साथ बिच्छीनारा के कक्ष क्रमांक 1348 पी. एफ में धूमण करने गया था। इस दौरान जंगल में ग्राम बिच्छीनारा के कई ग्रामीण वन भूमि पर अतिक्रमण करने के उद्देश्य से पोकलेन मशीन लगा कर समतलीकरण का कार्य कर रहे थे तथा वहां के पेड़-पौधों को भी नष्ट रहे थे। उन्हें जमीन समतलीकरण करते देख विजय कुमार मिंज ने पूछा कि इस काम के लिए किसी विभाग से आदेश प्राप्त किया है क्या?इस पर ग्रामीणों ने कहा कि हमारे जमीन को एनटीपीसी द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया है, जिससे अब हम लोग इस जमीन में अपना मकान बना कर रहेंगे। जब वनकर्मियों ने इस तरह

जंगल नष्ट कर अतिक्रमण नहीं करने की ग्रामीणों को समझाईश दी, जिससे आक्रोशित ग्रामीणों ने उनके साथ गाली-गलौच करते हुए अपने पास रखे कुल्हाड़ी, डंडा इत्यादि लेकर मारपीट करने का प्रयास किये। विजय कुमार मिंज व सुभाष कुमार कर्ष वहां से भाग कर किसी तरह अपनी जान बचाई।वहीं अपने मुख्यालय आकर उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को तदराश्य की जानकारी दी तथा अधिकारियों के निर्देश पर थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। वहीं पुलिस ने डिप्टी रेंजर विजय कुमार मिंज की रिफॉर्ट पर ग्राम बिच्छीनारा निवासी दयाराम चौहान, रामप्रसाद सारथी, परपित्त उरांव, बलराम उरांव, प्रमोद उरांव, कुमार उरांव सहित अन्य ग्रामीणों के विरुद्ध बीएनएस की धारा 191 (1), 191 (2), 190, 296, 351 (3), 221, 132 के तहत अपराध पंजीबद्ध करते हुए आगे की कार्रवाई प्रारंभ कर दी है।

संक्षिप्त समाचार

15 दिनों से बंद बिजली, सूखने की कगार पर फसल – हलिया गुडरीपारा के किसान परेशान



मूक पत्रिका/केशकाल – ग्राम हलिया गुडरीपारा में पिछले 15–16 दिनों से 11 केवी पावर सप्लाई में तकनीकी खराबी के कारण बिजली आपूर्ति पूरी तरह ठप है। लगातार बिजली बंद रहने से क्षेत्र के किसानों की फसलें सूखने की कगार पर पहुंच गई हैं, जिससे किसानों में भारी चिंता और नाराजगी देखने को मिल रही है। ग्रामीण किसानों का आरोप है कि वे कई बार बिजली विभाग के अधिकारियों से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन हर बार उन्हें केवल आश्वासन देकर टाल दिया जाता है। जब किसान अपनी समस्या लेकर विभागीय कार्यालय पहुंचे, तो कई बार अधिकारी वहां मौजूद ही नहीं मिले, जिससे उनकी परेशानी और बढ़ गई। किसानों ने बताया कि मजबूरी में उन्होंने मीडिया प्रतिनिधियों से संपर्क किया, जिसके बाद विभाग की ओर से जल्द मिस्त्री भेजकर सुधार करने की बात कही गई। हालांकि, आश्वासन के बावजूद अब तक समस्या का समाधान नहीं हो सका है और बिजली आपूर्ति बंद ही है। लगातार 15 दिनों से विभाग के चक्कर काट रहे किसान अब हताश और परेशान हैं। अपनी फसल बचाने के लिए वे अधिकारियों के सामने हाथ-पैर जोड़ने को मजबूर हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द से जल्द तकनीकी खराबी दूर कर बिजली आपूर्ति बहाल करने की मांग की है, ताकि उनकी फसल को बचाया जा सके और उन्हें आर्थिक नुकसान से राहत मिल सके।

बेमेतराइक्साजा ब्लॉक में पदाधिकारियों के चुनाव 25 व 26 अप्रैल को

मूक पत्रिका/बेमेतरा । प्रगतिशील छत्तीसगढ़ सतनामी समाज द्वारा संगठन विस्तार के तहत जिले के विभिन्न ब्लॉकों में पदाधिकारियों के चुनाव एवं मनोनयन की प्रक्रिया जारी है। इसी क्रम में बेमेतरा जिले के बेमेतरा एवं साजा ब्लॉक में चुनाव कार्यक्रम की तिथि घोषित कर दी गई है। जारी सूचना के अनुसार, 25 अप्रैल 2026 (शनिवार) को दोपहर 12 बजे से बेमेतरा ब्लॉक के वरिष्ठ, युवा एवं महिला प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों का चुनाव/मनोनयन, बहु नवागांव रोड स्थित गुरु बालक दास स्मृति स्थल सतनाम धाम बेमेतरा में संपन्न कराया जाएगा। वहीं 26 अप्रैल 2026 (रविवार) को साजा ब्लॉक के पदाधिकारियों का चुनाव संत भवन साजा में आयोजित होगा। इस संबंध में प्रदेश स्तर के पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसमें प्रदेश सहसचिव दिनेश बंजारे, प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीमती सुशीला सोनवानी एवं युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप श्रृंगी को निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न कराने की जिम्मेदारी दी गई है। कार्यक्रम के पश्चात संबंधित अधिकारियों को प्रदेश कार्यालय को सूचना प्रेषित करने के निर्देश दिए गए हैं। इस आयोजन को लेकर समाज के कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल देखा जा रहा है।

काँकेर में नि:शुल्क महिला स्वास्थ्य शिविर, गुरुवार 23 अप्रैल को स्वर्ण अवसर का लाभउठाएं,,,,

दैनिक मूक पत्रिका/ विक्रम ठाकुर /काँकेर:- काँकेर शहर तथा जिले के निवासियों के लिए यह एक प्रसन्नता का विषय और स्वर्ण अवसर ही कहा जाएगा कि आगामी गुरुवार 23 अप्रैल को पूंय्य सिंधी धर्मशाला मांझापारा काँकेर में भारत प्रसिद्ध वीमेंस हॉस्पिटल पहलाजानी टेस्ट ट्यूब बेबी (आईवीएफ) केंद्र द्वारा पूर्णतः नि:शुल्क महिला स्वास्थ्य शिविर का एकदिवसीय आयोजन किया गया है। जिसमें देश की प्रसिद्ध स्त्री रोग / नि: संतानता विशेषज्ञ डॉ रंरुति गजेंद्र, डॉक्टर निकिता गोकलानी तथा डॉक्टर मुस्कान लालवानी द्वारा महिलाओं की विभिन्न शारीरिक समस्याओं तथा नि: संतानता का उच्च- स्त्रीय परीक्षण एवं निदान किया जाएगा। चिकित्सा कार्यक्रम ठीक 10:00 बजे प्रारंभ होगा और 1:00 तक चलेगा, जिसमें स्थानीय लोकप्रिय सिंधी महिला विंग सुनहरे कदम तथा राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त समाजसेवी संस्था जन सहयोग का भी उल्लेखनीय योगदान होगा। संस्था के अध्यक्ष अजय पप्पू मोटवानी ने कहा है कि जिस प्रकार के चिकित्सा परीक्षण डायनोसिस के लिए बड़े शहरों में जाकर हजारों रुपए खर्च करने होते हैं, वही अब काँकेर में 23 अप्रैल को उपलब्ध है। आप इस महान सुविधा का लाभ उठाएं।

8 लाख के इनामी माओवादी ने किया आत्मसमर्पण, कांकेर पुलिस की बड़ी सफलता



दैनिक मूक पत्रिका/ विक्रम ठाकुर /काँकेर:- उत्तर बस्तर कांकेर जिले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बीते दिनों से चलाए जा रहे आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास अभियान के तहत एक इनामी माओवादी कैडर ने हिंसा का रास्ता छोड़ मुख्यधारा में लौटने का निर्णय लिया है। पुलिस अधीक्षक निखिल राखेचा ने बताया कि माओवादी संगठन के सदस्य लगातार आत्मसमर्पण कर रहे हैं।

इसी क्रम में 20 अप्रैल 2026 को PPCM दारसू शोरी (8 लाख रुपये इनामी) ने एके-47 के साथ आत्मसमर्पण किया। दारसू शोरी PLG कंपनी नंबर 05, उत्तर बस्तर डिवीजन से जुड़ा हुआ था। पुलिस के अनुसार, आत्मसमर्पण करने वाले कैडर से मिली जानकारी के आधार पर क्षेत्र में सक्रिय अन्य माओवादियों से संपर्क स्थापित कर उन्हें भी मुख्यधारा में शामिल कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पी. ने आत्मसमर्पण करने वाले माओवादी के निर्णय का स्वागत करते हुए शेष माओवादियों से भी हिंसा का मार्ग छोड़ समाज की मुख्यधारा में लौटने की अपील की है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जो लोग आत्मसमर्पण कर पुनर्वास चाहते हैं, उनके लिए शासन की योजनाओं के तहत पूरा सहयोग दिया जाएगा, जबकि हिंसा का रास्ता अपनाने वालों के खिलाफसख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

नेपाल से इंटरनेशनल जर्नलिज्म एक्सीलेंस अवॉर्ड प्राप्त टीम को जनसंपर्क आयुक्त रजत बंसल ने दी शुभकामनाएं

रायपुर। नेपाल दौर के दौरान इंटरनेशनल जर्नलिज्म एक्सीलेंस अवॉर्ड प्राप्त करने वाली पत्रकारों की टीम को आज जनसंपर्क आयुक्त रजत बंसल ने हार्दिक बधाइयाँ एवं शुभकामनाएँ दीं। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पत्रकारों और जनसंपर्क विभाग के बीच आपसी समन्वय और संवाद इसी तरह निरंतर बना रहेगा।

आयुक्त श्री बंसल ने टीम के इस अंतरराष्ट्रीय उपलब्धि को प्रदेश के लिए गौरवपूर्ण बताते हुए कहा कि पत्रकारिता के क्षेत्र में इस प्रकार की उपलब्धियाँ अन्य साथियों को भी प्रेरित करती हैं। उन्होंने सभी पत्रकारों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

इस दौरान इंडियन फेडरेशन ऑफ वरकिंग जर्नलिस्ट्स (आईएफडब्ल्यूजे) की टीम ने श्री बंसल को पशुपतिनाथ मंदिर से



लाए गए रुद्राक्ष, शॉल एवं प्रसाद भेंट कर

उनका सम्मान किया।



कार्यक्रम में पत्रकारों की टीम के

सदस्य प्रमुख रूप से उपस्थित रहे, जिनमें बिहान छत्तीसगढ़ की प्रधान संपादक ममता सिंह, दैनिक मूक पत्रिका के प्रधान संपादक आशीष कंठले, सर्वोच्च छत्तीसगढ़ के प्रधान संपादक शिवशंकर सोनपिपरे, भूपेश एक्सप्रेस के संपादक विप्लव दत्ता, एनसी न्यूज़ से प्रकाश केयर, ऑनलािक छत्तीसगढ़ के प्रधान संपादक विश्वजीत शाहा न्यूज़ नेशन हिंदी के संपादक विजय जय सिंधानी दूरदर्शन से धानी पटेल एवं एशियन न्यूज से भीष्म परिहार सहित अन्य पत्रकारगण मौजूद रहे।

कार्यक्रम का वातावरण आत्मीय एवं उत्साहपूर्ण रहा, जहाँ सभी ने इस उपलब्धि पर एक-दूसरे को बधाई दी और भविष्य में भी ऐसे ही सहयोग एवं संवाद बनाए रखने का संकल्प लिया।

महिला आरक्षण कब लागु होगा मोदी सरकार इस्पष्ट करें – अजय भाषवानी

दैनिक मूक पत्रिका/ विक्रम ठाकुर/ काँकेर :-काँकेर कांग्रेस विश्वो दलों के पूर्ण समर्थन से देश में सन 2023 को ही महिला आरक्षण बिल को पारित किया गया था। लेकिन देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण कब से लागू होगा, केंद्र सरकार पहले देश के सामने यह स्पष्ट करें।

मोदी सरकार पर उक्त सवाल दामते हुए आज जिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री अजय भाषवानी ने कहा कि संसद के विशेष सत्र में सन 2023 के महिला आरक्षण में संशोधन के लिए परिसीमन और जनगणना को जोड़ कर भाजपा अपनी राजनैतिक स्वार्थ को पूरा करना चाहती थी जिसे पूरे विपक्ष ने ध्वस्त कर दिया ,कांग्रेस नेता ने बताया कि संसद के वर्तमान 545 सीटों को बढ़ाकर परिसीमन में 850 सीट करने के बाद वे महिला आरक्षण को लागू करना चाहते थे। क्योंकि वे 2011



की जनगणना को आधार बनाकर इसीलिए परिसीमन करना चाहते थे क्योंकि उत्तर भारत जहां पर भाजपा अधिक मजबूत है वहां पर सीटों की संख्या अधिक हो जाती और दक्षिण, पूर्वी, उत्तर पूर्वी, उत्तर पश्चिम भारत के छोटे राज्यों में सीटों की संख्या तुलनात्मक रूप से कम हो जाती। उन्होंने मोदी सरकार पर अपनी राजनैतिक स्वार्थ को पूरा करने के लिए महिलाओं का उपयोग करने की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि अगर परिसीमन में उत्तर भारत में सीट बढ़

फिज़िक्सवाला (पीडब्ल्यू) ने JEE Main 2026 Session 2 के टॉपर्स की सफलता का बड़े स्तर पर जश्न मनाया

भिलाई : मंगलवार को देशभर के फिजिक्सवाला विद्यापीठ केंद्रों पर उत्सव का माहौल देखने को मिला, जहां हाल ही में घोषित JEE Main 2026 Session 2 परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले टॉपर छात्रों की सफलता का जश्न मनाया गया। शीर्ष स्कोरर्स में मुंबई के भायंदर के छात्र साहिल प्रधान शामिल रहे, जिनकी ऑल इंडिया रैंक (AIR) 94 है। प्रधान के अलावा, गुराशीश सिंह चड्ढा (AIR 112 – उत्तराखंड स्टेट टॉपर) और हरियाणा के नमन वर्मा, जो एक किसान के बेटे हैं और जिन्होंने ऑनलाइन ड्राइवर बैच से कुछ ही महीनों की तैयारी में AIR 243 हासिल की, जैसे छात्रों के प्रदर्शन का भी जश्न मनाया गया।

इसके अतिरिक्त, हेमाक्षी कुमार (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह), विष्णु भारद्वाज उपाध्याय (मेघालय) और रोहित शर्मा (हिमाचल प्रदेश) जैसे कई छात्रों ने अपने-अपने राज्यों में टॉप किया। प्रमोद यादव (99.85 – AIR 2476) और कुणाल देवांगन (99.75 – AIR 3995) भिलाई के पीडब्ल्यू विद्यापीठ के शीर्ष छात्रों में रहे। अलख पांडे, शिक्षक, संस्थापक एवं CEO, फिजिक्सवाला (पीडब्ल्यू) ने कहा, हम JEE Main 2026 में शामिल होने वाले सभी छात्रों पर गर्व करते हैं और विशेष रूप से उन छात्रों को बधाई देना चाहते हैं जिन्होंने उच्च अंक प्राप्त किए हैं। आपकी मेहनत और समर्पण सराहनीय है। जिन छात्रों को अपेक्षित परिणाम नहीं मिले, उनके लिए यह सिर्फ शुरुआत है। अपनी गलतियों का विश्लेषण करें, तैयारी को मजबूत करें और अपने लक्ष्य की ओर लगातार प्रयास करते रहें। हम आपको निरंतर सहयोग और मार्गदर्शन देते रहेंगे।

बेजुबान गौवंश के अस्तित्व और सम्मान की लड़ाई तेज

प्रशासन की कुम्भकर्णीय नींद के खिलाफबीडीसी दीपक सिंह दिनकर का मोर्चा, कलेक्टर कार्यालय की ओर कूच का ऐलान

मूक पत्रिका/बेमेतरा – क्षेत्र में बेजुबान गौवंश की बदहाल स्थिति को लेकर अब जनआक्रोश खुलकर सामने आने लगा है। लंबे समय से गौवंश की सुरक्षा, देखरेख और संरक्षण को लेकर उठ रही मांगों के बावजूद प्रशासनिक स्तर पर ठोस पहल न होने से लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है।

इसी कड़ी में बीडीसी सदस्य दीपक सिंह दिनकर ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि गौवंश की समस्या को लेकर कई बार जापन और आग्रह किए गए, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन ही मिला। उन्होंने इसे प्रशासन की कुम्भकर्णीय नींद बताते हुए कहा

कोरबा के फिजिक्सवाला छात्रों की सीबीएसई 10वीं बोर्ड 2026 में रिकॉर्ड सफलता

कोरबा: फिजिक्स वाला (पीडब्ल्यू) के कई विद्यार्थियों ने Central Board of Secondary Education (सीबीएसई) कक्षा 10 बोर्ड परीक्षा 2026 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए उच्च अंक प्राप्त किए। इनमें कुछ विद्यार्थियों ने शत-प्रतिशत (100%) अंक हासिल कर देश में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। पीडब्ल्यू विद्यापीठ-पाठशाला, जो फिजिक्सवाला के तकनीक-सक्षम हाइब्रिड केंद्र हैं, ने कोरबा में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया। इस समारोह में शहर के उन विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया जिन्होंने सीबीएसई कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा 2026 में उल्लेखनीय प्रदर्शन किया। दिशिता कृष्णा राव (98.80%), अन्वेषा सिंह (98.60%), पलक सिंह कुशवाहा (98.20%) और व्योम बघेल (98%) अन्य छात्रों के बीच उच्च प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों में शामिल रहे। परिणामों पर अपने विचार साझा करते हुए अलख पांडेय, संस्थापक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, फिजिक्सवाला (पीडब्ल्यू) ने कहा, हम परीक्षा में शामिल हुए सभी विद्यार्थियों को मेहनत की सराहना करते हैं। विशेष रूप से उन विद्यार्थियों को बधाई, जिन्होंने पूर्ण अंक हासिल किए। ये परिणाम निरंतर प्रयास और सही शैक्षणिक सहयोग प्रणाली को दर्शाते हैं। इस वर्ष सीबीएसई कक्षा 10वीं परीक्षा में 25 लाख से अधिक विद्यार्थी सम्मिलित हुए।



कि संवेदनशील मुद्दे पर इस तरह की वादा खिलाफी बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है।

दीपक सिंह दिनकर ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो वे गौ सेवकों और क्षेत्रवासियों के साथ मिलकर कलेक्टर कार्यालय की ओर कूच करेंगे। इस आंदोलन का उद्देश्य न केवल गौवंश की संरक्षण की मांग उठाना है, बल्कि

दैनिक मूक पत्रिका/ विक्रम ठाकुर/ काँकेर:- काँकेर भाजपा का महिला सशक्तिकरण का नारा महज एक ढकोसला निरूपित करते हुए नागरिक अधिकार रक्षा मंच के नेता नजीब कुरैशी ने बताया कि प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्र के नाम संदेश में जिस तरह से विरोधी राजनैतिक दलों को महिला विरोधी होने का झूठा प्रचार किया है वो निंदनीय है। जबकि वास्तविकता यह है कि भाजपा शासित राज्यों में महिलाओं के ऊपर अत्याचार में वृद्धि हुई है। उन्होंने राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि उत्तरप्रदेश में सबसे अधिक महिला उत्पीड़न का मामला दर्ज है। महिला उत्पीड़न का मामला दर्ज है। महिला उत्पीड़न के 66,381 मामले दर्ज हुए हैं जो देश के कुल दर्ज मामलों का 15 प्रतिशत है। भाजपा शासित महाराष्ट्र महिला उत्पीड़न के मामले



के विकास कार्यों को प्राथमिकता के साथ तेजी से पूरा करना आवश्यक है, ताकि आम नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। वहीं कलेक्टर ने

अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी विभाग आपसी समन्वय से कार्य करते हुए विकास की गति को बनाए रखें और जनता के विश्वास पर खरा उतरें।

भाजपा का महिला सशक्तिकरण का नारा महज एक ढकोसला - नजीब



में दूसरा स्थान पर है, जहा 47101 मामले दर्ज है। वही तीसरे स्थान पर राजस्थान जहां पर 454500 और चौथे स्थान पर भाजपा के ही शासित राज्य मध्यप्रदेश है जहां पर 32342 महिला उत्पीड़न की मामला दर्ज हुआ है। सन 2023 में पूरे देश में महिला उत्पीड़न की 4.3 लाख महिला उत्पीड़न की मामला दर्ज हुआ था

बच्चन आ रहे हैं – कलर्स ने जारी किया ‘बरेली के बच्चन’ का प्रोमो

हर परिवार में कुछ न कुछ खामियाँ होती हैं, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो अपने सजे-सवरे नकली चेहरे के पीछे की दरारों का सामना करने की हिम्मत रखते हैं। परिवार की इस मज्ददार उलझन को सामने लाते हुए कलर्स ने अपने नए ड्रामा ‘बरेली के बच्चन’ का प्रोमो रिलीज़ किया है। बरेली की चहल-पहल भरी गलियों में सेट यह शो एक व्यंग्यात्मक ज़िंदगी से जुड़ी कॉमेडी-ड्रामा है, जो दिखाता है कि एक घर कैसा बन जाता है जब वह सलों तक बिना किसी महिला के जीता है। इस शो में प्रविष्ट मिश्रा कृष्णा के किरदार में नज़र आएंगे – एक ऐसा शख्स जो आकर्षक है लेकिन टालमटोल करने वाला भी। शो वादा करता है धमाकेदार पारिवारिक टकराव और ऐसी कीमेडी जो इंसालिए असरदार लगती है क्योंकि वह असहज रूप से जानी-पहचानी लगती है। शो की स्टारकास्ट में रामनीक कटारिया के रूप में संगम, यशपाल शर्मा के रूप में अजब सिंह, किशुक महाजन के रूप में गंगा, संज मनुजा के रूप में सतलुज, और सचिन जीत सिंह के रूप में माही भी शामिल हैं।

[illegible]